बैंकों की स्थायी रूप से अनुदेश दिए गए हैं कि 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले समस्त ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर और 25,000/- रुपये से अधिक वालों का 8 से 9 सप्ताह में निपटान किया जाता है। आवेदनों का तीव्रता से निपटान करने के लिए कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों के ऋणों के लिए एक सरलीकृत ऋण देने संबंधी प्रक्रिया अपनाई गई है। बैंकों के समस्त शाखा प्रबंधकों को, किसी उच्च प्राधिकारी के बिना संदर्भ के ही कमजोर वर्गों से प्राप्त ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने की विवेकपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। ऋण के संवितरण में विलम्ब के संबंध में, यदि कोई शिकायतें होती हैं तो उन्हें सुधारात्मक उपायों के लिए संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

(ङ) और (च) : कृषकों को आसानी तथा समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों के चुनिंदा जिलों में, सरकारी क्षेत्र के कुछेक बैंकों ने अपनी मर्जी से परीक्षण के आधार पर कृषि ऋण कार्ड शुरु कर दिए हैं। ये कार्ड उन कृषकों को दिए जाते हैं, जिन का ट्रैक रिकार्ड अच्छा हो ताकि वे उत्पादन संबंधी निविष्टियों की लागत को पूरा कर सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 21 बैंकों ने महाराष्ट्र सहित, राज्यों के चुनिंदा जिलों में कृषि ऋण कार्ड योजना लागू कर दी है।

मशीनों के कलपुर्जों का मूल्य ह्रास

1947. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजियाबाद स्थित इंश्योरेंस यूनाईटेड कम्पनी के मंडल कार्यालय ने एक ही मशीन के कलपुर्जों का मूल्य ह्रास अलग-अलग निर्धारित किया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) मूल्य-ह्रास की राशियों के निर्धारण में अपनाए जा रहे नियमों का ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि उनके गाजियाबाद मंडल कार्यालय ने एक ही मशीन के कलपुर्जों के मूल्य ह्रास का अलग-अलग निर्धारण नहीं किया। इस संबंध में निर्दिष्ट सीमा के अनुसार मशीन के कलपुर्जों की आयु, हालत, अनुरक्षण, प्रति पादन तथा टूट फूट के अनुसार ही मूल्य ह्रास निर्धारित किए जाते हैं।

Viability Reports of the Non-viable Projects

1948. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the viability reports of the non-viable foreign aided projects were first prepared at the time of their inception to improve the disbursement of international assistance; and

(b) if so, what action Government has taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) No Sir.

(b) Question does not arise.